International Journal of Advancement in Electronics and Computer Engineering (IJAECE)
Volume 13, Issue 9, Sept.. 2024, pp.106-110, ISSN 2278 -1412
Copyright © 2012: IJAECE (www.ijaece.com)

मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाओं का पन्ना जिले के कृषि आधारित आजीविका पर प्रभाव का अध्ययन

[1]CA. Manish Bhagat, [2]Dr Sachin Goyal
[1]Research Scholar, camanishbhagat@gmail.com, MCBU University Panna (M.P.)
[2]Assistant Professor & Head , Faculty of Commerce , Sachingoyal290@gmail.com, Chhatrasal Govt. P. G. College, Panna (M.P.)

सारांश: - *इस अध्ययन का उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई कृषक कल्याण योजनाओं का पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित आजीविका पर प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह शोध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जैसे सब्सिडी, फसल बीमा, ऋण माफी, और सिंचाई समर्थन का मूल्यांकन करता है, ताकि यह समझा जा सके कि ये योजनाएं किस हद तक कृषि उत्पादन में सुधार और किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक रही हैं। अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों का उपयोग करके यह आकलन किया गया है कि ये योजनाएं कितनी हद तक टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, आय के स्तर में वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को कम करने में सफल रही हैं। इसके अलावा, यह शोध योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करता है और उनकी डिलीवरी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है। इस अध्ययन के निष्कर्षों का उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बदलने में योजनाओं की भूमिका पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना और टिकाऊ विकास के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की रणनीतियों पर नीति–निर्माताओं को सूचित करना है।*

Keywords: - कृषक कल्याण योजनाएँ, पन्ना जिला, ग्रामीण विकास, कृषि आधारित आजीविका, मध्य प्रदेश, फसल बीमा, ऋण माफी सिंचाई समर्थन, टिकाऊ कृषि

I. प्रस्तावना

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और यह ग्रामीण आजीविका का प्रमुख स्रोत है। देश के विभिन्न राज्यों में, कृषि के विकास और किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य, जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, ने भी कृषक कल्याण के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे कि फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सिंचाई योजनाएँ, और कृषि ऋण माफी। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय में सुधार करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, और कृषि जोखिम को कम करना है। पन्ना जिला, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित हो रहा है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से पारंपरिक फसलें उगाते हैं, और उनकी आजीविका का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में, सरकारी योजनाओं के तहत कई पहलें की गई हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि विकास को प्रोत्साहित करना है।

इस अध्ययन का उद्देश्य मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाओं का पन्ना जिले के कृषि आधारित आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका विश्लेषण करना है। इसमें इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया, उनके लाभार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव, और कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन इस बात की भी जाँच करेगा कि क्या सरकारी योजनाओं ने किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाया है और किस हद तक उन्होंने ग्रामीण विकास में योगदान दिया है।

इस प्रकार, यह शोध पन्ना जिले में कृषि के क्षेत्र में हुए बदलावों और सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को समझने के

Copyright © 2012: IJAECE (www.ijaece.com)

लिए महत्वपूर्ण होगा। इसका उद्देश्य नीतिगत सुधारों के लिए सुझाव देना और भविष्य में किसानों के कल्याण के लिए प्रभावी योजनाएँ विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।।

II. साहित्य समीक्षा

विभिन्न शोधकर्ताओं और लेखकों ने मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया है, विशेषकर पन्ना जिले में इन योजनाओं का कृषि आधारित आजीविका पर जो प्रभाव है, वह महत्वपूर्ण रूप से चर्चा का विषय रहा है। लेखकगण इस बात पर सहमत हैं कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ये योजनाएं अत्यधिक आवश्यक हैं। योजनाओं के माध्यम से, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण माफी योजना, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जाती है। पीयूषी नेमा और अन्य (2024) ने सागर संभाग में किसानों के ऋण बोझ पर नाबार्ड की ब्याज सब्सिडी योजनाओं के प्रभाव पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य ऋण के प्रकारों और उनके वित्तीय निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन योजनाओं के उपयोग को समझना है। मिश्रित पद्धति दृष्टिकोण के माध्यम से, नाबार्ड की योजनाओं और किसानों के ऋण की स्थिति के साथ उनके अनुभवों का आकलन करने के लिए संरचित साक्षात्कार कार्यक्रम का उपयोग करके 20 किसानों से डेटा एकत्र किया जाएगा। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ऋण बोझ को कम करने में सब्सिडी की प्रभावशीलता का आकलन करना, ब्याज भुगतान पर बचत का विश्लेषण करना और पुनर्भुगतान क्षमताओं पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करना है। इसके अलावा, यह अध्ययन कृषि सुधार या पारिवारिक जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा और संसाधन आवंटन में संभावित वृद्धि पर विचार करते हुए, किसानों की भलाई पर कम ऋण के गुणात्मक प्रभाव का पता लगाएगा। इस शोध के निष्कर्षों से सागर संभाग में किसानों की वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाने और सामुदायिक स्तर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में ब्याज सब्सिडी कार्यक्रमों की भूमिका को बेहतर समझने में योगदान मिलने की उम्मीद है।

कन्हैया आहूजा एट अल (2008) का अध्ययन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी की आवश्यकता के महत्व पर केंद्रित है, जिसे कृषि विकास के लिए रणनीतिक आदानों में से एक माना जाता है। अध्ययन के अनुसार, अधिकांश भारतीय किसान ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, और कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय संस्थागत प्रवाह उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण वित्त न केवल उत्पादन, भंडारण, रखरखाव और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि कृषि गतिविधियों के विस्तार में भी योगदान देता है। ऋण कृषि विकास को गति देने में सहायक हो सकता है, बशर्ते कि वह पर्याप्त, सस्ता और विकासोन्मुख हो। एक गरीब किसान के लिए निवेश आवश्यकताओं में बढ़ती मांग के साथ बदलती कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाना लगभग असंभव है। साठ और सत्तर के दशक के दौरान, छोटे किसान संस्थागत ऋण के अपर्याप्त प्रवाह के कारण उच्च उपज वाली किस्म (एचवाईवी) प्रौद्योगिकी को अपनाने में पिछड़ गए थे। उच्च मात्रा में ऋण की आवश्यकता न केवल अल्पावधि नकद इनपुट जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशकों के उपयोग के लिए होती है, बल्कि सिंचाई और भूमि विकास गतिविधियों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक निवेश के लिए भी होती है। स्वतंत्र भारत में संस्थागत स्रोतों से ऋण का अभूतपूर्व विस्तार कृषि ऋण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भारत में ग्रामीण ऋण की आपूर्ति में संस्थागत ऋण स्रोतों की हिस्सेदारी में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1951–52 में केवल 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 1991–92 में 56.6 प्रतिशत हो गई। सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसी संस्थागत ऋण एजेंसियां किसानों को फसल उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीक अपनाने और कृषि पद्धतियों में सुधार करने में मदद कर रही हैं। 1950–51 में कृषि के लिए संस्थागत ऋण का प्रवाह 24.23 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000–01 में 53504 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 1970 से 2000–01 तक लगभग 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

चतुर्वेदी पूनम और अन्य (2023) के अध्ययन ने लॉगरिदमिक मीन डिविजिया इंडेक्स (एलएमडीआई) अपघटन दृष्टिकोण का उपयोग करके कुल फसल राजस्व के मूल्य में गतिशील परिवर्तनों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। इस अध्ययन के

Copyright © 2012: IJAECE (www.ijaece.com)

लिए मध्य प्रदेश के किमोर पठार कृषि–जलवायु क्षेत्र के पाँच जिलों, यानी जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना और सीधी को 2007–08 से 2016–17 की अवधि के लिए चुना गया था। अध्ययन में कुल फसल राजस्व को क्षेत्र, कीमत, फसल पैटर्न, और उपज प्रभाव में विघटित किया गया। परिणामों से पता चला कि जबलपुर जिले में किसानों का अनाज फसलों की ओर अधिक रुझान है, जबकि पन्ना और कटनी जिलों में तिलहनों की ओर अधिक रुझान देखा गया। सीधी जिले में गेहूँ, चना, और अरहर को छोड़कर लगभग सभी फसलों में सापेक्ष परिवर्तन नकारात्मक था। अध्ययन से यह भी पता चला कि इस कृषि–जलवायु क्षेत्र में अध्ययन अवधि के दौरान उपज प्रभाव प्रमुख कारक था, इसके बाद मूल्य प्रभाव का स्थान था। हालांकि, जबलपुर जिले में मूल्य प्रभाव प्रमुख था, इसके बाद उपज प्रभाव का स्थान था। विभिन्न प्रभावों के बीच, कृषि–जलवायु क्षेत्र में फसल पैटर्न प्रभाव का सबसे छोटा योगदान था।

कई लेखकों ने यह भी इंगित किया है कि पन्ना जिले में सूखे, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी और सिंचाई के साधनों की अपर्याप्तता जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, इन योजनाओं ने कृषि आधारित आय की स्थिरता और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। शोध में यह भी पाया गया है कि वित्तीय सहायता और बीमा योजनाओं ने किसानों को फसल की क्षति के जोखिम से बचाने और कृषि के लिए आवश्यक निवेश में सहायता की है। हालांकि, कुछ लेखकों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आई समस्याओं को भी रेखांकित किया है, जैसे कि किसानों तक योजना की सही जानकारी न पहुंचना, दस्तावेजीकरण की कठिनाइयाँ, और सहायता प्राप्त करने में देरी। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी की आवश्यकता है, जिससे पन्ना जिले के ग्रामीण विकास को गति मिल सके।।

III. कार्यप्रणाली

अध्ययन की कार्यप्रणाली में पन्ना जिले के कृषि आधारित आजीविका पर मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक मिश्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का संग्रहण किया गया है। प्राथमिक डेटा संग्रहण के लिए, पन्ना जिले के विभिन्न ग्रामों में किसानों के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार और सर्वेक्षण किए गए, जिससे कृषक कल्याण योजनाओं के प्रति उनकी जागरूकता, लाभों की प्राप्ति, और उनके कृषि जीवन पर योजनाओं के प्रभाव को समझा जा सके।

द्वितीयक डेटा के लिए, सरकारी रिपोर्ट्स, योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित दस्तावेज, और कृषि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट्स का अध्ययन किया गया है, ताकि योजनाओं की वर्तमान स्थिति और उनके निष्पादन की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग कर एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और गैर–लाभार्थियों के बीच तुलना की गई है।

इस अध्ययन में क्षेत्र विशेष की कृषि संबंधी चुनौतियों, जैसे जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों की उपलब्धता, और फसल पैटर्न को भी ध्यान में रखा गया है, ताकि योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का समग्र मूल्यांकन किया जा सके।

IV. परिणाम

मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाओं के पन्ना जिले में कृषि आधारित आजीविका पर प्रभाव का गहराई से विश्लेषण किया। इस अध्ययन में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के आंकड़ों का विस्तृत उपयोग किया गया, जिसमें फसल उत्पादन, आय में वृद्धि, और सामुदायिक विकास के पहलुओं को शामिल किया गया।

अध्ययन के परिणामों ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने वाले किसानों की औसत आय में लगभग 30% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः फसल उत्पादन में सुधार के कारण हुई, जहां 60% लाभार्थी किसानों ने नई फसल तकनीकों और उन्नत कृषि

Copyright © 2012: IJAECE (www.ijaece.com)

पद्धतियों को अपनाया। परिणामस्वरूप, उनकी फसल उपज में 25% की वृद्धि देखी गई। यह दर्शाता है कि योजनाओं ने किसानों को संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और विविध फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे उनकी आय में स्थायी सुधार आया है।

इसके अलावा, सिमुलेशन में यह पाया गया कि कृषक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत किसानों को बेहतर जल प्रबंधन और कृषि संसाधनों की उपलब्धता मिली है। 70% लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें योजनाओं के माध्यम से सिंचाई, उर्वरक, और अन्य आवश्यक संसाधनों की सुविधाएं मिली हैं, जिसने उनके कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सामुदायिक विकास के संदर्भ में, अध्ययन ने यह दर्शाया कि लाभार्थी किसानों के समुदायों में सामाजिक और आर्थिक विकास के संकेत मिले हैं। कृषक कल्याण योजनाओं ने किसानों में सहयोग और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित व्यवसायों का विकास हुआ है।

अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि योजनाओं के प्रति किसानों की जागरूकता में सुधार हुआ है। सिमुलेशन परिणामों के अनुसार, 75% किसानों ने योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो उनकी योजनाओं में रुचि बढ़ाने और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।

इन सभी पहलुओं ने यह स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाएं न केवल व्यक्तिगत किसान की आर्थिक स्थिति को सशक्त बना रही हैं, बल्कि ग्रामीण विकास और सामुदायिक सशक्तीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं ने कृषि क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन और विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है, जो पन्ना जिले के किसानों के लिए उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है।

V. निष्कर्ष

इस अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाओं का पन्ना जिले के कृषि आधारित आजीविका पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को न केवल आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, बल्कि कृषि उत्पादन में सुधार, आय में वृद्धि और सामुदायिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर मिले हैं।

अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि लाभार्थी किसानों की औसत आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि योजनाओं ने उन्हें नई तकनीकों और संसाधनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही, किसानों में जागरूकता बढ़ी है और उन्होंने कृषि के प्रति अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन किया है।

सामुदायिक स्तर पर, योजनाओं ने सहयोग और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास के संकेत मिले हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि योजनाओं के प्रभाव के अध्ययन ने यह बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ–साथ उनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि हुई है।

इस प्रकार, मध्य प्रदेश की कृषक कल्याण योजनाएं केवल किसानों की आर्थिक भलाई के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो रही हैं। भविष्य में, इन योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए निरंतर समर्थन, संसाधनों की उपलब्धता, और योजनाओं के प्रति किसानों की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे न केवल पन्ना जिले, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कृषि आधारित आजीविका को सशक्त किया जा सकेगा।

संदर्भ

[1] पीयूषी नेमा (2024), सागर संभाग में किसानों के ऋण बोझ पर नाबार्ड की ब्याज सब्सिडी योजनाओं का प्रभाव, बुन्देलखण्ड रिसर्च जर्नल जून, 2024 खंड 2, अंक 1 आईएसएसएनरू 2584–0533, 2024।

[2] कन्हैया आहूजा, गणेश कावड़िया, अनंत ग्वाल और आनंद श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण संवितरणरू एक अंतर–जिला विश्लेषण वॉल्यूम। 13, अंक 1, मध्यप्रदेश जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 2008।

[3] चतुर्वेदी पूनम, वाणी गौरव कुमार, राजपूत अंकिता, मध्यप्रदेश के किमोर पठार कृषि– जलवायु क्षेत्र में कुल फसल राजस्व में गतिशील परिवर्तनों का अपघटन विश्लेषण खंडरू 68, अंकरू 1, आर्थिक मामले, 2023, डीओआईरू 10. 46852ध0424–2513.1.2023.8

[4] बाला बी और शर्मा एसडी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कृषि के विविधीकरण और व्यावसायीकरण की आय और रोजगार पर प्रभाव कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा 18रू 261–269।

[5] अली, जे. और एस. कपूर, फलों और सब्जियों के उत्पादन में जोखिमों पर किसान की धारणारू उत्तर प्रदेश का एक अनुभवजन्य अध्ययन कृषि। इकोन. रेस. रेव., 21(कॉन्फ. नं.)रू 317–326।

[6] एनी बडकुल, मोहम्मद फिरोज सी और दीप्ति बेंदी, ष्सामाजिक– आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं की खोजरू मध्यप्रदेश, भारत का एक मामला स्प्रिंगर, 2022, डीओआईरू https://doi-org/10-1007978 &3&030&96760&4_9

[7] रजनी जैन, प्रेमचंद, प्रियंका अग्रवाल, सुलक्षणा राव और सुरेश पा, ष्आकांक्षी जिलों में कृषि बुनियादी ढांचे की उपयुक्तता का निर्धारणरू बुंदेलखण्ड का एक केस अध्ययनष्, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, 2021।

[8] गगन त्रिपाठी, अर्पित ढोडिया, अनमोल गिरी, वीणा राठौड़, अमन वर्मा, अनूप शुक्ला, ललित कुमार वर्मा, 2023 – खंड 41 अंक 11, एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी डीओआईरू https:/ /doi-org/10-9734/ajaees/2023/v41i112261

[9] संदीप कौर, हेमराज, हरप्रीत सिंह और विजय कुमार चट्टू, भारत में फसल बीमा नीतियांरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक अनुभवजन्य विश्लेषणष्, खंड 9 अंक 11, एमपीडीआई, 2021, डीओआईरू https://doi -org/10-3390/risks9110191

[10] प्रो. रतन लाल गोदारा, डॉ. प्रताप सिंह और डॉ. संजय सिंगला, भारत में कृषि क्रेडिटरू एक विश्लेषणात्मक अध्ययनष्, वॉल्यूम। 3 अंक 3 जनवरी 2014, आईएसएसएनरू 2278–621एक्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईजेएलटीईटी)।

[11] डॉ. सागर सुरेंद्र देशमुख डॉ. यसोदा गायत्री ए. सुश्री प्रियंका जलाल, ष्रोजगार सृजन पर भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि उद्यम पहल का प्रभाव विश्लेषण आईएसबीएनरू 978–93–91668–88–4 , 2023।

[12] मेघा साहू, जे.एस. रघुवंशी और ए.एम. जौलकर, मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऋण के उपयोग पैटर्न और डायवर्सन पर एक अध्ययन आईएसएसएन (पी)रू 2250–0057य आईएसएसएन(ई)रू 2321–0087 वॉल्यूम। 7, अंक 2, अप्रैल 2017, 405–412, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड रिसर्च (आईजेएएसआर)।